$ 1.1 billion in June, 1991 to about US $ 5 billion by March 1992 and are being maintained at that level. With the introduction of unified exchange rate, it is expected that Balance of Payments position would improve further.

Levy of Wealth Tax in Jammu and Kashmir

1640 SHRI JAGMOHAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Supreme Court of India has recently ruled that Wealth Tax is leviable in the State of Jammu and Kashmir;

(b) if so, what is the number of cases where Wealth Tax has now become recoverable; and

(c) what is the amount involved and other material particulars of the cases ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The number of cases where wealth tax has now become recoverable in the state of Jammu & Kashmir and the amount involved is as under :

Provisional figures as on 31st January, 1993

(i) No. of cases	1172
(ii) Arrear demand outstanding	Rs. 2.60 crores

The above demand could not be recovered due to the judgement of the Hon'ble Jammu & Kashmir High Court declaring the wealth-tax Act ultra-vires in the state of Jammu & Kashmir. The decision has now been reversed by the Hon'ble Supreme Court and steps as per law are being taken to recover this demand.

दसवें वित्त आयोग द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश

1641. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को क्या क्या निदेश जारी किये गये हैं; और

(ख) उन पर राज्यों की प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा क्या है

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 280 (1) के अन्तर्गत गठित वित्त आयोग एक स्वतन्त्र निकाय है न कि केन्द्रीय सरकार का अंग है । इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 280 (4) के अन्तर्गत आयोग अपने कार्य की पद्धति स्वयं निर्धारित करता है । इसलिए, यह भारत सरकार की कार्यकारी शक्तियों के दायरे में नहीं आता है ।

विदेशी ऋण

1642. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत पर इस समय किन-किन देशों और किन किन वित्तीय संस्थाओं का ऋण बकाया है और ऐसे ऋणों की धन राशि का ब्यौरा क्या है और

(ख) उपर्युक्त ऋणों पर प्रत्येक वर्ष ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । (नीचे देखिए) ।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान बकाया ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि 7356 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।

विवरण

30-9-92 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण

करोड़ रुपए

क्रम सं०	देश	30-9-92 तक बकाया ऋण
1	2	3
	सरकारी लेखा	
1	बाई० डी० ए०	21904.83
2	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक	20246.01
3	ओपेक	273.13
4	आई० एस० ओ०	17.12
5	इटली	431.84
6	एशियाई विकास बैंक	1662.24
7	संयुक्त राज्य अमेरिका	7122.33
8	ईरान	246.86
9	स्पेन	137.95
10	संयुक्त अरब अमीरात	29.99
11	आई० डी० ए०	19184.90
12	आई० एफ० ए० डी०	536.43
13	स्वीडन	279.07
14	स्विटजरलैण्ड	123.76
15	स्वीडन	365.54
16	तऊदी निधि	221.46
17	चैकोस्लोवाकिया	51.46
18	यू० एस० एस० आर०	3011.16
19	यूरोपीय आर्थिक समुदाय (एस० ए० सी०)	151.92
20	यू० के०	520.08
21	कुवैत निधि	458.39
22	जापान	13712.95
23	फ्रांस	3959.03
24	आबूधाबी निधि	12.66
25	इटली	292.49
26	जर्मनी	11194.48
27	डेनमार्क	502.38
28	नीदरलैण्ड्स	3319.68
29	कनाडा	1526.78
30	बेल्जियम	344.61
31	आस्ट्रिया	181.04
	जोड (सरकारी लेखे)	112022.58

1	2	3
गैर सरकारी लेखा		
1	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक . . .	3272.26
2	एशियाई विकास बैंक	1164.38
3	फ्रांस	169.20
4	जर्मनी	1009.15
	जोड़ (गैर सरकारी लेखा) . . .	5614.99
	कुल जोड़ :	117637.57

Bank Loans to Handloom Sector

1643. SHRI RAMNARESH YADAV : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have given loan to handloom sector on easy terms through Public Sector Banks for providing employment to the unemployed persons in this sector and for making these industries viable;

(b) if so, what is the amount of assistance that has been provided during the last two years till date of the handloom industry;

(c) what are the area-wise details thereof; and

(d) whether banks have formulated any plan for their development if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) to (d) In terms of guidelines issued by the Reserve Bank of India, the Public Sector Banks are to ensure that advances to weaker sections, which include Artisans, Village and Cottage Industries should be at least 10 percent of their total advances or 25 per cent of their priority sector advances. The advances extended to Artisans, Village and Cottage industries cover handloom sector also. The data collecting system does not generate the information about the amount of advances extended by public sector banks separately under handloom sector. The total outstanding advances of public sector banks to Artisans, Village and Cottage industries as at the end of September, 1989, September, 1990 and March, 1991 (latest available) were as under :—

As at the end of	No. of Accounts	Amount (Rs in crores)
September, 1989	1478725	659·62
September, 1990	2424597	754·07
March, 1991	1472603	724·11

बकों में खेतों का कम्प्यूटरीकरण

1644. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक समूह की उन शाखाओं के नाम और पते क्या है जिनमें बचत खातों/चालू खातों का समस्त काम कम्प्यूटर के द्वारा किया जाता है और उन शेष शाखाओं के नाम क्या है जिनमें अभी तक कम्प्यूटर नहीं लगाया गया है।

(ख) क्या भारतीय स्टेट बैंक समूह द्वारा बचत खाता धारकों की